कलकत्ता क्रोमोटाइप लिमिटेड,

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता

मार्च 31, 1998

[न्यायाधिपति श्रीमती सुजाता वी. मनोहर और डी.पी. वाधवा]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944-धारा 4(1)(ए), परंतुक (iii) और धारा 4(4)(सी)-एक ही परिवार द्वारा धारित दो अलग-अलग कंपनियां-उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का उचित मूल्यांकन-"संबंधित व्यक्ति"- का अर्थ है-धारित, निर्माता और खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं होने चाहिए और बिक्री के लिए माल की कीमत ही एकमात्र विचार होनी चाहिए।

कॉर्पोरेट कानून- कॉर्पोरेट पर्दा हटाना- निर्माता और खरीदार के कुछ निश्चित संबंधों पर कोई रोक नहीं-साथ ही उनके बीच किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित को निश्चित करना-हालाँकि, कोई व्यापक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश - "संबंधित व्यक्ति" - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944-धारा 4 के संदर्भ में अर्थ।

**अपीलकर्ता कंपनी ताश के पत्ते बनाती है, और पूरा स्टॉक अपने एकमात्र वितरकों को बेचती है। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने उस कीमत पर शुल्क लगाया जिस पर अपीलकर्ता कंपनी ने अपने एकमात्र**

वितरक को ताश के पत्ते बेचे थे, क्योंकि धारा 4(4)(सी) के अर्थ के तहत एकमात्र वितरक "संबंधित व्यक्ति" था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम. अपील कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि एकमात्र वितरक अपीलकर्ता का संबंधित व्यक्ति था। अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता न्यायाधिकरण के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जिसने अपील कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि अपीलकर्ता-निर्माता और एकमात्र वितरक के बीच हितों की पहचान थी और माना गया कि सहायक कलेक्टर ने परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेयर ब्रेक-अप पर विचार नहीं किया था। इसलिए, मामले को ब्रेक-अप पर विचार करने और पहचान के परीक्षण से संतुष्ट होने पर आदेश की पुष्टि करने के लिए सहायक कलेक्टर को भेज दिया गया था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि संबंधित व्यक्ति होने के लिए, निर्धारिती के व्यवसाय में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना चाहिए और वर्तमान मामले में दोनों कंपनियां स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे के साथ एक दूरी पर सौदा करती हैं; कि एक ही परिवार द्वारा शेयरों की संयुक्त हिस्सेदारी हित की पहचान निर्धारित करने के लिए एक कमजोर परीक्षण थी; यह दिखाने के लिए कोई आरोप, निष्कर्ष या सबूत नहीं है कि दोनों कंपनियां स्वतंत्र नहीं थीं या एक दूसरेके साथ अनुकूल व्यवहार कर रही थी; और यह कि बाद के वर्षों में विभाग ने एकमात्र वितरक को संबंधित व्यक्ति नहीं माना।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभीनिर्धारित: 1. जब एक ही परिवार के पास विनिर्माण कंपनी और खरीदार के शेयर हों, तो उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन करने के लिए, एक-दूसरे के हितों की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट पर्दा हटाकर किया जा सकता है।[575-एफ]

2.1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) के तहत, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य सामान्य मूल्य नहीं होगा, जो कि वह कीमत है जिस पर सामान आमतौर पर निर्धारिती द्वारा खरीदार को बेचा जाता है, यदि खरीदार एक है "संबंधित व्यक्ति" और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है।[584-डी-ई]

2.2. अधिनियम की धारा 4 उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। नकारात्मक रूप से कहें तो, यह मूल्यांकन के उद्देश्य से सामान्य कीमत नहीं होगी, यदि खरीदार एक संबंधित व्यक्ति है और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है।[576-एच; 578-एफ]

3. सिद्धांत यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी एक अलग पहचान है और इसलिए, जहां निर्माता और खरीदार दो अलग-अलग कंपनियां हैं, वे वे किसी भी चीज़ से अधिक 'संबंधित व्यक्ति' नहीं हो सकते हैं, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) खंड (सी) के अर्थ में

सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। प्राधिकारियों पर किसी कंपनी, चाहे वह निर्माता हो या खरीदार, से यह पर्दा उठाने पर कोई रोक नहीं है कि उसने यह मुखौटा नहीं पहना है कि उसे संबंधित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, जबकि वास्तव में निर्माता और खरीदार दोनों एक ही व्यक्ति हैं। [581-डी]

4. न केवल निर्माता और खरीदार दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता है ताकि यह देखा जा सके कि इसके पीछे कौन है, बल्कि यह भी है कि उन्हें एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित होना चाहिए। लेकिन एक बार जब यह पता चल जाता है कि निर्माता और खरीदार के पीछे के लोग एक ही हैं, तो यह स्पष्ट है कि खरीदार निर्माता से जुड़ा हुआ है: यानी, निर्धारिती और फिर प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, यह माना जा सकता है कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है। हालाँकि, किसी भी व्यापक सिद्धांत को निर्धारित करना मुश्किल है कि कॉर्पोरेट पर्दा कब हटाया जाना चाहिए या यदि ऐसा किया जाता है, तो क्या यह कहा जाएगा कि निर्धारिती और खरीदार संबंधित व्यक्ति हैं। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और यह देखना होगा कि निर्धारिती और खरीदार दोनों में से कौन फैसला ले रहा है। जब यह वही व्यक्ति हो, तो अधिनियम की धारा 4(i) के खंड (ए) का

तीसरा प्रावधान लागू होगा। उत्पाद शुल्क अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए आगे की जांच करने से कभी नहीं रोका जाता है कि दो कंपनियों के पीछे कौन व्यक्ति है, जिनमें से एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माता है और दूसरा उन वस्तुओं का खरीदार है, और दोनों कंपनियां एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं, किसी भी अन्य व्याख्या की तरह संकीर्ण हो सकती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।[584-एफ-एच]

5. मौजूदा मामले में अधिकारियों और अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती और खरीदार दोनों की शेयर होल्डिंग्स के मूल प्रश्न पर खुद को संबोधित किया। यह पाया गया कि दोनों कंपनियों के शेयर 'शर्मा परिवार' के सदस्यों के पास थे। अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों कंपनियों में परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेयरों के बंटवारे को निश्चित करने का निर्देश देने में आंशिक रूप से सही था। पर्दा उठाने के लिए दोनों कंपनियों की वास्तविक शेयरधारिता और दोनों कंपनियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को "हित की पहचान" पर विचार करने के लिए निश्चित होना आवश्यक है। हालाँकि, अधिकारियों ने अपीलकर्ता और उसके एकमात्र वितरक को संबंधित व्यक्तियों के रूप में नहीं माना है, जिसके तथ्य का प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है और अधिकारियों ने बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल के रूप में उस कीमत को स्वीकार कर लिया है जिस पर निर्धारिती द्वारा एकमात्र वितरक को सामान बेचा जाता है। मामला वर्ष

1976 का है और सहायक कलेक्टर का आदेश वर्ष 1978 का है। इस देर के

**चरण में निर्धारिती, अपीलकर्ता और उसके एकमात्र वितरक की शेयर होल्डिंग्स की जांच करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता।[585-ई-एच; 586-ए]**

भारत संघ एवं अन्य बनाम एटीआईसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [1984] 3 एससीसी 575; कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास बनाम टी.आई. मिलर्स लिमिटेड, मद्रास; और टी.आई. डायमंड चेन, मद्रास, [1988] सप्लिमेंट. एससीसी 361; स्नो व्हाइट औद्योगिक निगम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (1989) 41 ईएलटी 360 एससी; मेसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, [1985] 3 एससीसी 230; टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, ए [1964] 6 एससीआर 885 और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य, [1986] 1 एससीसी 264, पर भरोसा किया गया।

महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1991) 53 ईएलटी 120 (ट्रिब्यूनल) और वीकफील्ड प्रोडक्ट्स सीटी (भारत) बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, (1993) 63 ईएलटी 672 (ट्रिब्यूनल), अनुपयुक्त ठहराया गया।

सैल्मन बनाम ए. सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, (1897) एसी 22 एचएल और आईआरसी बनाम ड्यूक ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, (1936) एसी 1, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 241-42/1991

सीमा शुल्क के निर्णय और आदेश दिनांक 30.10.89, 30.7.90 उत्पाद शुल्क विभाग सोना (नियंत्रण) से। अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में ए. क्रमांक ई/बीओएम/ क्रमांक 483/81ए, 13/90-ए.

दुष्यन्त दवे, सुश्री मंजू मिश्रा और के.जे. जॉन अपीलकर्ता की ओर से।

एस.डी. शर्मा और वी.के. वर्मा प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**न्यायाधिपति डी.पी. वाधवा** मैसर्स. कलकत्ता क्रोमोटाइप लिमिटेड ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षिप्त अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए) के 30 अक्टूबर 1989 के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। इस निर्णय के द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखते हुए पाया कि यद्यपि अपीलकर्ता, निर्माता और मैसर्स गंगा सरन एंड संस प्रा. लिमिटेड, इसके एकमात्र वितरक के बीच हितों की पहचान थी, सहायक कलेक्टर ने निर्माता और वितरक के परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेयरों

के बंटवारे पर विचार नहीं किया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि यह तथ्य है कि हित की पहचान ही निर्धारक कारक थी यह जानने में कि क्या कोई व्यक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4(4)(सी) के अर्थ के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति है (संक्षेप में 'अधिनियम' के लिए)। चूंकि सहायक कलेक्टर ने निर्माता और वितरक दोनों कंपनियों वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेयरों के बंटवारे पर विचार नहीं किया था, ट्रिब्यूनल ने परिवार के प्रत्येक सदस्य के शेयरों के बंटवारे पर विचार करने के लिए मामले को सहायक कलेक्टर को भेज दिया और यदि "पहचान का परीक्षण" संतुष्ट था, तो उसे आदेश की पुष्टि करनी चाहिए।

अपीलकर्ता ताश का निर्माण करता है। यह अपने द्वारा निर्मित ताश के पत्तों का पूरा स्टॉक अपने एकमात्र वितरक मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड को बेचता है। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने अधिनियम के तहत उस कीमत पर शुल्क लगाया जिस पर मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताश के पत्ते बेचे गए थे क्योंकि सहायक कलेक्टर के अनुसार अपीलकर्ता के अधिनियम की धारा 4(4)(सी) के अर्थ के भीतर यह संबंधित व्यक्ति था। अपील कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड अपीलकर्ता का संबंधित व्यक्ति था। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता ने संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 36

के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और उसके बाद पुनरीक्षण आवेदन को अपीलीय न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और अपील के रूप में सुना गया।

सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने पाया कि अपीलकर्ता और उसके एकमात्र वितरक दोनों कंपनी अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनियां थे। उन्होंने पाया कि इन दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल का गठन किया गया था:

"अपीलकर्ता

1. श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रबंध निदेशक

2. श्रीमती. ब्रह्मा देवी, निदेशक

3. श्रीमती. इंदु शर्मा, निदेशक

मैसर्स गंगा सरन एंड संस कंपनी

1. श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रबंध निदेशक

2. श्रीमती. ब्रह्मा देवी, निदेशक

3. श्री ब्रजेन्द्र शर्मा, निदेशक

4. श्री राजेंद्र शर्मा, निदेशक"

सहायक कलेक्टर ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता और उसके एकमात्र वितरक के शेयर शर्मा परिवार के सदस्यों के पास थे। यानी, ऐसे व्यक्ति जो एक-दूसरे से संबंधित थे और दोनों कंपनियों में सामान्य प्रबंध निदेशक थे

और इसके अलावा अपीलकर्ता अपने वितरक के ब्रांड नाम, अर्थात् मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सामान बेच रहा था। ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील दी गई कि दोनों कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत थीं और अलग-अलग कानूनी अधिकार थे और इसलिए, उन्हें संबंधित व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सामान्य निदेशक का होना यह निर्धारित करने वाला कारक नहीं था कि मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड एक संबंधित व्यक्ति था। और इसके अलावा तथ्य यह है कि निर्माता खरीदार का नाम छाप रहा था और खरीदार को पूरा उत्पाद बेच रहा था खरीदार को संबंधित व्यक्ति भी नहीं बनाया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि नीचे दिए गए अधिकारी यह स्थापित करने में विफल रहे कि मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड को अनुकूल व्यवहार दिया गया था और वास्तव में, उस खाते पर कम कीमत वसूल की गई थी। अपीलकर्ता ने कहा कि ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में यह मानना सही नहीं था कि जिस कीमत पर मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पाद बेचा, वह मूल्य निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से थी।

अधिनियम की धारा 4(4)(सी) के संदर्भ में अपीलीय न्यायाधिकरण का यह भी विचार था कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारिती के साथ जुड़ा हुआ है और वे एक-दूसरे के व्यवसाय में हित रखते हैं तो धारा के अर्थ के अंतर्गत वह व्यक्ति दूसरे का संबंधित व्यक्ति था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा

कि कलेक्टर (अपील) ने माना था कि अपीलकर्ता के साथ-साथ मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत और स्थापना जीएस शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी और इसके अलावा सहायक कलेक्टर ने पाया था कि अपीलकर्ता के शेयर और क्रेता कंपनी के शेयर एक ही शर्मा परिवार के सदस्यों के पास थे और इस प्रकार, यह उन व्यक्तियों के पास थे जो एक-दूसरे से संबंधित थे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के निर्णय मोहनलाल मगन लाल भावसार (मृत) जरिए एलआरएस और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य, (1986) 23 ईएलटी 3 का हवाला दिया और अपने स्वयं के फैसले डायमंड क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम सीसीई पुणे, (1988) 34 ईएलटी 662 का भी उल्लेख किया, जहां इसने संबंधित व्यक्ति की परिभाषा की व्याख्या की। इस मामले के तथ्यों पर लागू इन दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार था कि वहां हित की पहचान थी और मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड अधिनियम की धारा 4(4)(सी) के अर्थ के तहत संबंधित व्यक्ति था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निपटारा कर दिया।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री दवे ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मानकर गलती की है कि अपीलकर्ता और मैसर्स गंगा सरन एंड संस प्रा. लिमिटेड संबंधित व्यक्ति थे या कि दोनों के बीच हित की पहचान थी। उन्होंने कहा कि दो फैसले, एक सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा

अपीलीय न्यायाधिकरण का, जिस पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने भरोसा किया था, लागू नहीं थे क्योंकि उक्त दोनों मामलों में तथ्य पूरी तरह से अलग थे और निर्णय स्पष्ट रूप से अलग थे। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 4(4)(सी) के अर्थ के तहत एक संबंधित व्यक्ति होने के लिए जिस व्यक्ति पर संबंधित होने का आरोप लगाया गया है, उसका निर्धारिती के व्यवसाय और वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित होना चाहिए। मामले में अपीलकर्ता और उसके खरीदार दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थीं, जो ताश के पत्तों पर उत्पाद शुल्क लगाने से बहुत पहले स्थापित की गई थीं और एक-दूसरे के साथ दूरी बनाकर काम कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दोनों कंपनियों में से प्रत्येक में शेयरधारिता के बारे में कोई सबूत नहीं था और यह कहना कि शेयरधारिता शर्मा परिवार के पास थी, एक मिथ्या नाम है और इस तरह के नाजुक परीक्षण को हितों की पहचान या पारस्परिकता का परीक्षण करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। श्री दवे ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया यह मानकर गलत निष्कर्ष पर पहुंचा कि शर्मा परिवार ने दोनों कंपनियों को नियंत्रित किया है। शर्मा परिवार एक अस्पष्ट शब्द है और इसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि दोनों कंपनियों में सदस्यों की सटीक हिस्सेदारी क्या थी और वे एक-दूसरे से कैसे संबंधित थे। अंत में, श्री दवे ने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है और न ही ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि अपीलकर्ता और उसके वितरक के बीच लेन-देन

एक-दूसरे से दूरी पर नहीं था या जिस कीमत पर वितरक को सामान बेचा गया था वह असाधारण रूप से कम था, कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक विचारों से प्रभावित था। श्री दवे ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और वहां लागू कानून की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की और इसके कारण उसे ऐसे निर्देश देने पड़े जो गलत हैं और अब उन पर आपत्ति जताई जा रही है।

श्री दवे ने यह भी प्रस्तुत किया कि बाद के वर्षों में विभाग ने यह विचार किया कि खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया। इन निर्णयों का संदर्भ लेने से पहले, हम अधिनियम की धारा 4 के प्रासंगिक प्रावधानों को दोबारा प्रस्तुत कर सकते हैं:

"4. उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन:-

(1) जहां इस अधिनियम के तहत, मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, ऐसा मूल्य, इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन माना जाएगा-

(ए) उसकी सामान्य कीमत, यानी वह कीमत जिस पर थोक व्यापार के दौरान करदाता द्वारा सामान को हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए खरीदार को आम तौर पर ऐसे सामान बेचे जाते हैं, जहां खरीदार

नहीं होता है संबंधित व्यक्ति और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचारणीय है:

उपलब्ध कराया-

(i)...

(ii)...

(iii) जहां निर्धारिती ऐसी व्यवस्था करता है कि सामान आम तौर पर थोक व्यापार के दौरान उसके द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से नहीं बेचा जाता है, निर्धारिती द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बेची गई वस्तुओं की सामान्य कीमत वह कीमत मानी जाएगी जिस पर वे थोक व्यापार के दौरान डीलरों को हटाने के समय संबंधित व्यक्ति द्वारा आम तौर पर बेची जाती हैं (संबंधित व्यक्ति नहीं होना) या जहां ऐसे सामान ऐसे डीलरों को नहीं बेचे जाते हैं, उन डीलरों (संबंधित व्यक्ति होने के नाते) को जो खुदरा में ऐसे सामान बेचते हैं;

(बी)...

(2)...

(3)...

(4) या इस धारा का उद्देश्य:-

(ए) "निर्धारिती" का अर्थ वह व्यक्ति है जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

(सी) "संबंधित व्यक्ति" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्धारिती के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है और इसमें एक होल्डिंग कंपनी, एक सहायक कंपनी, एक रिश्तेदार और निर्धारिती का एक वितरक शामिल है, और ऐसे वितरक का कोई उप-वितरक।

स्पष्टीकरण- इस खंड में "होल्डिंग कंपनी", "एक सहायक कंपनी" और "रिश्तेदार" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में है

(डी)...

(इ)...

नकारात्मक रूप से कहें तो, यह मूल्यांकन के उद्देश्य से सामान्य कीमत नहीं होगी, यदि खरीदार एक संबंधित व्यक्ति है और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है। दोनों स्थितियाँ सह-अस्तित्व में होनी चाहिए ताकि जिस कीमत पर निर्मित माल करदाता द्वारा खरीदार को बेचा जाता है उसे उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से मूल्य के रूप में लिया जाए। धारा 4(4) के खंड (सी) के अर्थ में "संबंधित व्यक्ति" कौन है, इस न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम एटीआईसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, [1984] 3 एससीसी 575 में कहा:

"परिभाषा के पहले भाग में यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को 'संबंधित व्यक्ति' के रूप में ब्रांड करने की मांग की गई है, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निर्धारिती के साथ इतना जुड़ा हो कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित हो। यह पर्याप्त नहीं है कि निर्धारिती का कथित संबंधित व्यक्ति के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित है और न ही यह पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति पर संबंधित व्यक्ति होने का आरोप लगाया गया है, उसका करदाता के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है। परिभाषा के पहले भाग की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारिती और कथित संबंधित व्यक्ति का एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित होना चाहिए। उनमें से प्रत्येक का दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना चाहिए। दूसरे के व्यवसाय में प्रत्येक की समानता और हित की डिग्री भिन्न हो सकती है; एक का दूसरे के व्यवसाय में हित प्रत्यक्ष हो सकता है, जबकि दूसरे के व्यवसाय में दूसरे का हित अप्रत्यक्ष हो सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,

जब तक प्रत्येक को दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हित प्राप्त है।"

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास बनाम टी आई मिलर्स लिमिटेड मद्रास और टी आई डायमंड चेन, मद्रास, [1988] सप्लीमेन्ट्री एससीसी 361 के बाद के मामलों में इसका पालन किया गया; स्नो व्हाइट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1989) 41 ईएलटी 360 एससी। यह भी बताया गया कि इस न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील (सिविल अपील संख्या 9850/95, 4 अप्रैल 1996 को निर्णय) में इसे खारिज कर दिया था। जहां अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना था कि खरीदार और विक्रेता के बीच भागीदारों और निदेशकों की समानता ही खरीदार को 'संबंधित व्यक्ति' के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है, भले ही पूरा उत्पादन उनके माध्यम से बेचा गया हो। हमने सीए 9850/95 की फाइल की जांच की है। जो पाया गया वह यह था कि अपील राजस्व द्वारा दायर की गई थी जो परिसीमा द्वारा वर्जित थी और देरी को इस शर्त पर माफ कर दिया गया कि उत्तरदाताओं के वकील को चार सप्ताह के भीतर 500 रुपये का भुगतान करना होगा। चूंकि लागत का भुगतान नहीं किया गया था इसलिए अपील को 4 अप्रैल, 1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया

गया था। इसलिए, अपील को खारिज करने से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आदेश में, जिसे सीए 9850/95 में लागू किया गया था, पाया कि निर्धारिती ने 96 में से 95 लैंप एक ऐसी कंपनी को बेच दिए थे, जिसमें निर्धारिती फर्म का एक भागीदार निदेशक था। इस पर विभाग ने यह विचार किया कि कंपनी एक संबंधित व्यक्ति थी और माल का मूल्यांकन उस उच्च कीमत पर करना चाहा, जिस पर निर्धारिती ने खरीदार कंपनी को माल बेचा था। अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार था कि केवल इसलिए कि निर्धारिती और कंपनी के बीच कुछ सामान्य निदेशक थे, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा कि दोनों संबंधित व्यक्ति थे। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पाया कि निर्धारिती द्वारा खरीदार कंपनी को माल की बिक्री को छोड़कर ब्याज की पारस्परिकता के संबंध में कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। इसमें कहा गया है कि हालांकि बिक्री का यह तथ्य निर्धारिती फर्म के व्यवसाय में कंपनी की एकतरफ़ा हित पैदा कर सकता है, लेकिन यह खरीदार कंपनी के व्यवसाय में निर्धारिती की हित का संकेत नहीं है।

महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, [1991 (53) ईएलटी 120 (ट्रिब्यूनल)] और वीकफील्ड प्रोडक्ट्स कंपनी (भारत) बनाम कलेक्टर या सेंट्रल एक्साइज [1993 (63) ईएलटी 672 (ट्रिब्यूनल)] मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के दो आदेशों का भी संदर्भ दिया गया था। पहले मामले में, निर्धारिती के चार में से तीन

निदेशक इसके थोक खरीदार मेसर्स वेस्टर्न इंडिया क्लास वर्क्स के निदेशक भी थे। ट्रिब्यूनल ने पाया कि यह विभाग का मामला नहीं था कि मेसर्स वेस्टर्न इंडिया ग्लास वर्क्स के अलावा अन्य ग्राहकों को बिक्री मेसर्स वेस्टर्न इंडिया ग्लास वर्क्स की बिक्री की कीमतों से अलग कीमतों पर थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि हितों की पारस्परिकता जैसे किसी अन्य कारक की अनुपस्थिति में, कुछ निदेशकों की समानता उन दो कंपनियों के बीच संबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो सामान्य स्वतंत्र कॉर्पोरेट कानूनी अधिकार थीं। दूसरे मामले में, निर्धारिती ने अपना माल दो व्यापक चैनलों के माध्यम से बेचा, अर्थात सीधे कैंटीन स्टोर्स विभाग और वीकफील्ड सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन को। जबकि कैंटीन स्टोर्स विभाग को 20% छूट की अनुमति दी गई थी, वीकफील्ड सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन को 30% छूट की अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने एक मामले में अधिक छूट की अनुमति देने के कारण को उचित ठहराया क्योंकि विभाग का मानना था कि निर्धारिती और वीकफील्ड सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच लेनदेन को गलत नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फर्म के अधिकांश भागीदार निर्धारिती के निदेशकों के करीबी रिश्तेदार थे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी थी। अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार था कि निर्धारिती एक कॉर्पोरेट कंपनी है और वीकफील्ड सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक साझेदारी कंपनी है, उत्तरार्द्ध को निर्धारिती का रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता

है और वीकफील्ड सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन को एक पसंदीदा खरीदार के रूप में मानने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि विशेष रूप से कम कीमत वसूल की गई थी।

राजस्व के वकील श्री शर्मा ने मोहनलाल मगनलाल भावसार (मृतक) थ्रू एलआरएस एंड आदि, बनाम 'यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य, (1986) 23 ELT 3 एससी आदि मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया। इस मामले में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि अपीलकर्ता की तैयारियों का थोक मूल्य अधिनियम की धारा 4 के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं लिया जा सकता है जिस कीमत पर इन्हें अपीलकर्ता के मुख्य वितरक मेसर्स एम बी भावसार एंड संस को आपूर्ति की गई थी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> "अपीलकर्ताओं का अगला तर्क, उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से औषधीय तैयारियों के मूल्य का निर्धारण करने में था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। इस पर अधिकारियों ने उक्त तैयारियों का थोक मूल्य लेने में गलती की, न कि वह कीमत जिस पर उक्त फर्म द्वारा उनके मुख्य वितरक मेसर्स एमबी भावसार एंड संस को आपूर्ति की गई थी। इस विवाद की सत्यता का परीक्षण करने के लिए

कुछ तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है जो मामले के इस पहलू के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेसर्स एमबी भावसार एंड संस की फर्म, हालांकि एक अलग साझेदारी फर्म थी, वास्तव में एक फर्म थी जिसमें न केवल मूल प्रथम अपीलकर्ता और अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 भागीदार थे, बल्कि उनमें से प्रत्येक का एक बेटा भी भागीदार था। इस प्रकार मेसर्स एमबी भावसार एंड संस और फर्म मेसर्स भावसार केमिकल वर्क्स के बीच हितों की पहचान हुई। इन दोनों फर्मों के कार्यालय एक ही परिसर में थे और साझेदारी समझौते के तहत मूल प्रथम अपीलकर्ता के बेटों और अन्य दो अपीलकर्ताओं को केवल मेसर्स एमबी भावसार एंड संस के मुनाफे में हिस्सा लेना था, लेकिन किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं थे। इसलिए, इन दोनों फर्मों को एक-दूसरे से दूर या स्वतंत्र पार्टियां नहीं कहा जा सकता है और जिस कीमत पर भावसार केमिकल वर्क्स द्वारा मेसर्स एमबी भावसार एंड संस को औषधीय तैयारी की आपूर्ति की गई थी, उसे उक्त तैयारी का वास्तविक मूल्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज करके सही किया।"

सिद्धांत यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी एक अलग इकाई है और, इसलिए, जहां निर्माता और खरीदार दो अलग-अलग कंपनियां हैं, वे, किसी भी चीज़ से अधिक, 'संबंधित व्यक्ति' नहीं हो सकते हैं, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (सी) के अर्थ में सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है। सॉलोमन बनाम सॉलोमन (1897) एसी 22 के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले के बाद कानून में काफी प्रगति हुई है। इस न्यायालय ने टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1964] 6 एससीआर 885 में इस तरह देखा।

"किसी निगम या कंपनी के चरित्र के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति, जो एक वैधानिक प्राधिकारी के साथ निगमित होती है, संदेह या विवाद में नहीं है। कानून में निगम एक प्राकृतिक व्यक्ति के बराबर है और उसकी अपनी एक कानूनी इकाई है। निगम की इकाई उसके शेयरधारकों से पूरी तरह अलग है; इसका अपना नाम है और इसकी अपनी मुहर है; इसकी संपत्तियां इसके सदस्यों से अलग और अलग हैं; यह विशेष रूप से अपने उद्देश्य के लिए मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है; इसके लेनदार इसके सदस्यों की संपत्ति से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते; सदस्यों या शेयरधारकों का दायित्व उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित है; इसी प्रकार, सदस्यों के लेनदारों का निगम की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी, (1897) एसी

22 एचएल, 1987 में फैसला सुनाए जाने के बाद से यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित हो गई है; वास्तव में, यह सदैव सामान्य कानून का सर्वमान्य सिद्धांत रहा है। हालाँकि, समय के साथ, यह सिद्धांत कि निगम या कंपनी की अपनी एक कानूनी और अलग इकाई है, कल्पना के अनुप्रयोग द्वारा कुछ अपवादों के अधीन किया गया है। निगम का पर्दा उठाया जा सकता है और उसके चेहरे की असलियत में जांच की जा सकती है। पर्दा हटाने का सिद्धांत इस प्रकार उस रवैये में बदलाव का प्रतीक है जिसे कानून ने मूल रूप से निगम की अलग इकाई या व्यक्तित्व की अवधारणा के प्रति अपनाया था। आर्थिक कारकों की जटिलता के प्रभाव के परिणामस्वरूप, न्यायिक निर्णयों ने कभी-कभी निगम के न्यायिक व्यक्तित्व के बारे में नियम के अपवादों को मान्यता दी है। ऐसा हो सकता है कि समय के साथ इन अपवादों की संख्या बढ़ जाए और विभिन्न आर्थिक समस्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम के व्यक्तित्व के बारे में सिद्धांत को अधिक से अधिक सीमित किया जा सके।

*भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य,* [1986] 1 एससीसी 264 में, इस न्यायालय ने फिर से इस प्रश्न पर विचार किया और कहा:

"हालांकि यह सॉलोमन बनाम ए, सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897) एसी 22 एचएल के बाद से दृढ़ता से स्थापित है, यह निर्णय लिया गया था कि किसी कंपनी का एक स्वतंत्र और कानूनी व्यक्तित्व होता है जो

उसके सदस्यों से अलग होता है, तब से यह माना जाता है कि कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता है, कॉर्पोरेट व्यक्तित्व को नजरअंदाज किया जा सकता है और कुछ असाधारण परिस्थितियों में व्यक्तिगत सदस्यों को पहचाना जा सकता है कि वे कौन हैं। पेनिंगटन ने अपने कंपनी कानून (चौथा संस्करण) में कहा है:

> "कंपनियों के अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत पर कानून द्वारा चार रास्ते बनाए गए हैं। अब तक इनमें से सबसे व्यापक कराधान लगाने वाला कानून बनाया गया है। सरकार, स्वाभाविक रूप से, कराधान से बचने के लिए योजनाओं को स्वेच्छा से बर्दाश्त नहीं करती है, जिनकी सफलता अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत के रोजगार पर निर्भर करती है, और वास्तव में कानून इतना आगे बढ़ गया है कि कुछ परिस्थितियों में कराधान अधिक भारी हो सकता है यदि करदाता द्वारा अपनी कर देनदारी को कम करने के प्रयास में कंपनियों को नियोजित किया जाता है, बजाय इसके कि यदि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करता है। कंपनियों का कराधान एक जटिल विषय है, और इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। जो पाठक इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें निगम

कर, आयकर, पूंजीगत लाभ कर और पूंजी हस्तांतरण कर पर कई मानक पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ दिया जाता है।

दूसरा अलग कॉरपोरेट के सिद्धांत पर अतिक्रमण कंपनी अधिनियम, 1948 की दो धाराओं द्वारा उस सिद्धांत की न्यायिक अवहेलना करके एक व्यक्तित्व बनाया गया है, जहां सार्वजनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है, या जहां कंपनी का गठन कानून द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया गया है, और अदालतों द्वारा कुछ मामलों में यह कहा जाता है कि एक कंपनी अपने सदस्यों के लिए एक एजेंट या ट्रस्टी है।

पामर के कंपनी कानून (23 वें संस्करण) में, इंग्लैंड में वर्तमान स्थिति बताई गई है और उन अवसरों की गणना की गई है जब कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता है और उन्हें चौदह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह गोवर्स कंपनी लॉ (चौथा संस्करण) में, एक अध्याय 'पर्दा उठाने' के लिए समर्पित है और विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई है जब ऐसा किया जा सकता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड

लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड [1964]6 एससीआर 885 में, कंपनी चाहती थी कि कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जाए ताकि कंपनी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दायर की गई याचिका के रूप में मानकर उसकी रखरखाव को बनाए रखा जा सके। कंपनी के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए कंपनी को एक नागरिक के रूप में मानना संभव नहीं था। सीआईटी बनाम श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, एआईआर (1967)एससी819 में, कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया गया और कानूनी पहलू के पीछे की आर्थिक वास्तविकताओं पर ध्यान देकर आयकर की चोरी को रोका गया। वर्कमेन बनाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड [1985]4 एससीसी114 में, कल्याणकारी कानून से बचने के लिए उपकरणों को रोकने के लिए पर्दा उठाने के सिद्धांत का सहारा लिया गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि लेन-देन के स्वरूप को नहीं, बल्कि सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आम तौर पर और मोटे तौर पर, हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट पर्दा उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून स्वयं पर्दा उठाने पर

विचार करता है, या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा रखता है, या एक कर क़ानून या लाभकारी क़ानून से बचने की कोशिश की जाती है या जहां संबद्ध कंपनियाँ वास्तव में एक ही संस्था का हिस्सा होने के नाते अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। उन मामलों की श्रेणियों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है जहां पर्दा उठाने की अनुमति है, चूँकि यह आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, विवादित आचरण, सार्वजनिक हित के तत्व की भागीदारी, प्रभावित होने वाले पक्षों पर प्रभाव आदि पर निर्भर होना चाहिए।"

मैसर्स मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी [1985] 3 एससीसी 230 = (1985) 154 आईटीआर 148 में, इस न्यायालय ने कर से बचने की अवधारणा या बल्कि कानून को तोड़े बिना कर से बचने की कला की वैधता की जांच की। इस न्यायालय ने आईआरसी बनाम ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, (1936) एसी 1 के मामले में लॉर्ड टॉमलिन की टिप्पणी के आधार पर वेस्टमिंस्टर सिद्धांत से हटने की आवश्यकता पर जोर दिया कि प्रत्येक करदाता अपने मामलों को

व्यवस्थित करने का हकदार है, जिस पर कर नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि टैक्स प्लानिंग वैध हो सकती है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। हालाँकि, रंगीन उपकरण कर नियोजन का हिस्सा नहीं हो सकते। वास्तव में आय पर करों के भुगतान से बचने के लिए चालाकी या छल का सहारा लेने वाले संदिग्ध तरीकों की आज किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किए गए शानदार काम के रूप में सराहना और वैधीकरण नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी निंदा की जानी चाहिए और कठोरतम दंड से दंडित किया जाना चाहिए। यदि हम सभी निर्णयों के गहनता की जांच करें, तो अधिकारियों पर किसी कंपनी का पर्दा उठाने पर कोई रोक नहीं है, चाहे निर्माता हो या खरीदार, यह देखने के लिए कि उसने संबंधित व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं किए जाने का मुखौटा नहीं पहना है, जबकि वास्तव में, निर्माता और खरीदार दोनों, वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य उसकी सामान्य कीमत नहीं माना जाएगा, अर्थात, वह कीमत जिस पर थोक व्यापार के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदार को सामान को हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए आम तौर पर बेचा जाता है, यदि खरीदार एक संबंधित व्यक्ति है और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है। संबंधित व्यक्ति कौन है, इसकी परिभाषा हमें अधिनियम की धारा 4(4)(सी) में देखनी होगी। बात केवल यह नहीं है कि निर्माता और खरीदार दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता

है ताकि यह देखा जा सके कि इसके पीछे कौन है, बल्कि यह भी है कि उन्हें एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित होना चाहिए। लेकिन एक बार जब यह पता चलता है कि निर्माता और खरीदार के पीछे के लोग एक ही हैं, तो यह स्पष्ट है कि खरीदार निर्माता के साथ जुड़ा हुआ है, यानी निर्धारिती और फिर प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 देखें). हालाँकि, किसी भी व्यापक सिद्धांत को निर्धारित करना मुश्किल है कि कॉर्पोरेट पर्दा कब हटाया जाना चाहिए या यदि ऐसा करने पर, क्या यह कहा जा सकता है कि निर्धारिती और खरीदार संबंधित व्यक्ति हैं। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और यह देखना होगा कि करदाता और खरीदार दोनों में से कौन फैसला ले रहा है। जब यह वही व्यक्ति हो तो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य पर पहुंचने के लिए अधिकारी निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 4(1) के खंड (ए) के तीसरे प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब एक ही व्यक्ति दो कंपनियों को शामिल करता है जिनमें से एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माता है और दूसरा उन वस्तुओं का खरीदार है, दोनों कंपनियां अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, इसलिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए आगे कुछ भी जांच करने से रोक

दिया गया है कि ये दोनों कंपनियां कौन व्यक्ति हैं। ऐसी संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार करना कठिन है। यह सच है कि किसी कंपनी में शेयरधारिता बदल सकती है, पर्दा उठाने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या दोनों कंपनियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कानून विशिष्ट है कि जब उत्पाद शुल्क उस सामान पर उसके मूल्य के संदर्भ में लगाया जाता है, तो सामान्य कीमत जिस पर सामान बेचा जाता है, उसे प्रदान किया गया मूल्य माना जाएगा (1) खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं है और (2) कीमत ही एकमात्र विचारणीय है। यह एक मान्य प्रावधान है और मामले को धारा 4(1) के खंड (ए) के अंतर्गत आने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 4(4) अधिनियम के खंड (सी) के अर्थ के भीतर संबंधित व्यक्ति कौन है। पुनः यदि कीमत ही एकमात्र विचार नहीं है, तो उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य पर पहुंचने के लिए धारा 4(1) का खंड (ए) फिर से लागू नहीं होगा।

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों ने करदाता और खरीदार दोनों की शेयरधारिता के मूल प्रश्न पर खुद को संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि दोनों कंपनियों के प्रबंध निदेशक एक ही थे और एक अन्य निदेशक सामान्य था। यह भी पाया गया कि दोनों कंपनियों के शेयर 'शर्मा परिवार' के सदस्यों के पास थे लेकिन यह काफी अस्पष्ट अभिव्यक्ति है और इसलिए, हमारे विचार में, अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों कंपनियों में परिवार

के प्रत्येक सदस्य के शेयरों के बंटवारे का पता लगाने का निर्देश देने में आंशिक रूप से सही था। पर्दा उठाने के लिए दोनों कंपनियों की वास्तविक शेयरधारिता और दोनों कंपनियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को एक-दूसरे के व्यवसाय में दोनों कंपनियों के हित की पहचान पर विचार करने के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तथ्यात्मक आंकड़ों के बिना एक-दूसरे के व्यवसाय में हितों की ऐसी पारस्परिकता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें बताया गया है कि बाद के वर्षों के लिए, अधिकारियों ने अपीलकर्ता के एकमात्र वितरक मेसर्स गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड को संबंधित व्यक्ति के रूप में नहीं माना है, इस तथ्य का प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है और जिस कीमत पर माल निर्धारिती द्वारा एकमात्र वितरक को बेचा जाता है उसे बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल के रूप में स्वीकार कर लिया है। मामला साल 1976 का है। सहायक कलेक्टर का आदेश वर्ष 1978 का है। हमें नहीं लगता कि इस अंतिम चरण में अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार निर्धारिती, अपीलकर्ता और उसके एकमात्र वितरक की शेयरधारिता की जांच करने का कोई उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलीय न्यायाधिकरण के आक्षेपित

फैसले को रद्द कर दिया जाता है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति.

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **श्रीमती अनिता शर्मा** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)